

SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



I j d k j } k j k i f j o k j f u ; k s t u d h t k u d k j h , o a y k H k ç n ; k s t u k v k a d k
ç H k k o % , d v è ; ; u

y { e h { | g } शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
v f [k y s k d e k j x { r k } (P h . D .) समाजशास्त्र विभाग
शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE**Corresponding Authors**

y { e h { | g } शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
v f [k y s k d e k j x { r k } (P h . D .) समाजशास्त्र विभाग
शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी)
महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/02/2023

Revised on : ----

Accepted on : 20/02/2023

Plagiarism : 01% on 06/02/2023



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

Overall Similarity: **1%**

Date: Feb 6, 2023

Statistics: 19 words Plagiarized / 1428 Total words

Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.



' k s / k | k j

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा परिवार नियोजन की जानकारी एवं लाभप्रद योजनाओं का प्रभाव : एक अध्ययन करना है। भारत देश की तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। इस हेतु सरकार की ओर से अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिला एवं पुरुष नसबंदी सेवा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दी जा रही है साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जागरूकता अभियानों के कारण जागरूकता बढ़ी है। शोध पत्र हेतु शोधकर्ता द्वारा शोध समस्या को ध्यान में रखते हुए अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप और वर्णनात्मक शोध प्ररचना का सम्मिलित रूप से उपयोग किया है। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को चुनते हुए ग्वालियर जिले के 30 (15 शहरी तथा 15 ग्रामीण) पुरुषों का चयन किया गया। संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु स्व-निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। समकों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में ज्ञात होता है कि घर में परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी देने शासन या अस्पताल की ओर से कोई नहीं आता है, वहीं लोगो ने परिवार नियोजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।

e q ; ' k ç n

I j d k j } i f j o k j f u ; k s t u } t k u d k j h } ; k s t u k

ç L r k o u k

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है और वर्तमान में इन योजनाओं को पुनः गति भी मिली

है, फलस्वरूप इसे ऐच्छिक रखते हुए सकारात्मक तरीके से बढ़ावा देना दिन-प्रतिदिन संभव हो रहा है। यद्यपि परिवार नियोजन कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और वर्तमान तक प्राप्त उपलब्धियों की विवेचना की जायें, तो स्थिति निराशाजनक ही प्रतीत होती है। भारतीय समाज में व्याप्त निरक्षरता, अंधविश्वास, अज्ञानता, अधिक संतानों को प्रतिष्ठाजनक मानना, पुत्र प्राप्ति की लालसा, परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग से संबंधित भ्रांतियाँ आदि कारणों से आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

भारत दुनिया में पहला देश है जिसने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। ऐतिहासिक शुरुआत के बाद से परिवार नियोजन कार्यक्रम में नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार परिवर्तन किया है तथा वर्तमान में इस कार्यक्रम को न केवल जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुनर्स्थापित किया गया है बल्कि यह कार्यक्रम प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा भी देता है, इसके साथ-साथ मातृ, शिशु और बाल मृत्यु दर एवं रोग दर को भी कम करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए "हम दो हमारे दो" के सिद्धांत पर कायम रहकर पति-पत्नी दो बच्चों से अधिक सन्तान नहीं चाहते हैं और परिवार को नियोजित करने के लिए नसबन्दी या अन्य तरीके अपनाकर परिवार का नियोजन करते हैं।

ifjokj fu; kstu ds dkj .k

1. cPpkads tle ea i ; klr vUvj j [kuk% एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने में तीन साल से पाँच साल का अन्तर रखना उत्तम रहता है वर्ना माँ और बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती है, उनकी अकाल मौत तक हो सकती है।
2. ifjokj dks l hfer djuk% यानि छोटा परिवार बनाना।

ifjokj fu; kstu dh ; kst uk; a

स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिला एवं पुरुष नसबन्दी सेवा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दी जा रही है साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जागरूकता अभियानों के कारण जागरूकता बढ़ी है। महिला व पुरुष नसबन्दी परिवार नियोजन का एक स्थाई साधन है लेकिन व्यक्ति अस्थायी साधनों से भी परिवार नियोजन अपना सकता है। अस्थायी साधनों में कॉपर-टी, खाने वाली गोली (माला-एन व छाया) तथा निरोध शामिल है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक महिला या पुरुष में से कोई भी नसबन्दी करवा सकता है, लेकिन अब तक पुरुषों ने महिलाओं को आगे किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होने वाले नसबन्दी आपरेशन में 90 प्रतिशत संख्या महिलाओं की होती है, जबकि पुरुषों की संख्या महज 10 प्रतिशत रहती है। पुरुषों की नसबन्दी बिना चीरा-टांका होती है, जबकि महिलाओं की नसबन्दी के लिए कट लगाया जाता है। पुरुष नसबन्दी पर दो हजार रुपए और महिला को 1400 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव के एक सप्ताह के अंदर कोई महिला नसबन्दी करवाती है तो 2200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

'kkèk ds mís ;

1. शासन की ओर से परिवार नियोजन संबंधी जानकारी देने का अध्ययन करना।
2. परिवार नियोजन से संबंधित लाभप्रद योजनाओं का अध्ययन करना।

'kkèk fofèk

शोधकर्ता द्वारा शोध समस्या को ध्यान में रखते हुए अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप और वर्णनात्मक शोध प्ररचना का सम्मिलित रूप से उपयोग किया है।

vè; ; u {ks=

इस शोध कार्य हेतु मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को चुना गया है।

U; kn' k

इस शोध कार्य हेतु ग्वालियर जिले के 30 पुरुषों का चयन किया गया जिनमें 15 ग्रामीण एवं 15 शहरी पुरुष हैं।

'kkək mi dj .k

सरकार द्वारा परिवार नियोजन की जानकारी एवं लाभप्रद योजनाओं का प्रभाव से संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु स्व-निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

I kf [; dh fofək

समकों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है।

rF; kədk fo' yšk.k

rkyfkd Ø- 1% क्या घर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी देने शासन या अस्पताल की ओर से कोई आता है?

क्र.	विकल्प	संख्या		कुल	प्रतिशत
		श.	ग्रा.		
(अ)	हाँ	3	2	5	16.67
(ब)	नहीं	9	11	20	66.67
(स)	कभी नहीं	3	2	5	16.67
योग		15	15	30	100.00

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका क्र. 1 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 30 उत्तरदाताओं से यह पूछने पर क्या आपके घर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी देने शासन या अस्पताल की ओर से कोई आता है? तो इसके प्रति उत्तर में हाँ में 05 (03 शहरी एवं 02 ग्रामीण) (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने एवं नहीं में 20 (09 शहरी एवं 11 ग्रामीण) (66.67 प्रतिशत) तथा कभी नहीं में 05 (03 शहरी एवं 02 ग्रामीण) (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जवाब दिया। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने माना कि घर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी देने शासन या अस्पताल की ओर से कोई नहीं आता है।

rkyfkd Ø- 2% क्या आपने परिवार नियोजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है?

क्र.	विकल्प	संख्या		कुल	प्रतिशत
		श.	ग्रा.		
(अ)	हाँ	11	9	20	66.67
(ब)	नहीं	4	6	10	33.33
योग		15	15	30	100.00

(स्रोत: प्राथमिक समंक)

उपरोक्त तालिका क्र. 2 का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 30 उत्तरदाताओं से यह पूछने पर क्या आपने परिवार नियोजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है? तो इसके प्रति उत्तर में हाँ में 20 (11 शहरी एवं 09 ग्रामीण) (66.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने एवं नहीं में 10 (04 शहरी एवं 06 ग्रामीण) (33.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जवाब दिया। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने माना है कि उन्होंने परिवार नियोजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।

fu"d"kl

शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं ने यद्यपि भारत में बाल मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, पर अब सबसे अधिक वंचित समूहों तक पहुंच बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए; बालिकाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां देश में एसएनसीयू के तेजी से बढ़ते स्तर से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, वही इससे नवजात कन्या की देखभाल करने में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं भी सामने आई हैं।

शोध की प्रथम परिकल्पना के अनुसार शासन की ओर से परिवार नियोजन संबंधी जानकारी दी जाती है अस्वीकृत होती है क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के घर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की जानकारी देने शासन या अस्पताल की ओर से कोई नहीं आता है।

द्वितीय परिकल्पना के अनुसार परिवार नियोजन से संबंधित योजनाओं का लोगों द्वारा लाभ लिया जाता है। स्वीकृत होती है क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने परिवार नियोजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।

I pko

- शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन योजना की जानकारी निरन्तर पहुंचानी चाहिए।
- पुरुष एवं महिला दोनों को ही परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना चाहिए।
- पुरुष एवं महिलाओं को परिवार नियोजन संबंधी योजनाओं के विषय में जानकारी रखना चाहिए।
- ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर परिवार नियोजन योजना की जानकारी स्पष्ट तौर पर बोर्ड, पैम्पलेट्स आदि में दर्शाकर लोगों में वितरण करना चाहिए।
- शासन द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के लाभ शहरी एवं ग्रामीण लोगों को समय-समय पर बताना चाहिए।

I nHkZ I yph

1. चाकले ए.एम., (2003), *परिवार नियोजन और परिवार कल्याण*, आगरा।
2. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., (2019), *समाजशास्त्र*, आगरा।
3. कपिल एच.के., (2010), *अनुसंधान विधियाँ*, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2010।
4. www.parivarniyogan.org
